भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
22.03.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3677 का उत्तर

सिवनी-कटंगी रेल लाइन का सर्वेक्षण

3677. डॉ. ढाल सिंह बिसेन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरी की गई नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण के बाद व्यवहार्य पाए गए रेल मार्गों का ब्यौरा क्या हैं और जिन रेल लाइनों को व्यवहार्य पाया गया है उन पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सिवनी बालाघाट जिले में किसी रेल मार्ग का सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसे व्यवहार्य पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सिवनी से कटंगी रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और यदि हां, तो इसकी व्यवहार्यता की स्थिति क्या है;

(च) क्या इसके विस्तृत सर्वेक्षण के लिए अनुमति दिए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

सिवनी-कटंगी रेल लाइन के सर्वेक्षण के संबंध में 22.03.2023 को लोक सभा में डॉ. ढाल सिंह बिसेन के अतारांकित प्रश्न सं. 3677 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार , भारतीय रेल में , लगभग 4.0 लाख करोड़ रुपये की लागत की कुल 20,937 किलोमीटर लंबाई की 183 नई लाइन परियोजनाएं योजना/स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं , जिनमें से 2,831 किलोमीटर लंबाई कमीशन हो चुकी है और मार्च , 2022 तक लगभग 1.13 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2019-20 , 2020-21, 2021-22 और (2022-23 फरवरी, 2023 तक), भारतीय रेल में 2565 किलोमीटर नई लाइन खंड कमीशन किए गए हैं।

लागत, व्यय और परिव्यय सहित परियोजना का क्षेत्रीय-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in> Ministry of Railways> Railway Board> about Indian Railways>Railway Board Directorates> Finance (Budget)> Rail Budget/Pink Book (year)> Railway-wise Works, Machinery and Rolling Stock Programme (RSP) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2019-20 , 2020-21, 2021-22 और चालू वित्त वर्ष 2022-23 (फरवरी, 2023 तक) में , देश भर में कुल 19 ,778 किलोमीटर की लंबाई की नई लाइनों के लिए 286 सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं और 102 परियोजनाएं (21 नई लाइन , 13 आमान परिवर्तन और 68 दोहरीकरण) कुल 3 ,177 किलोमीटर की लंबाई 43,959 करोड़ रु. की लागत से स्वीकृत की गई हैं।

रेल परियोजना(ओं) का समय पर पूरा होना विभिन्ना कारकों जैसे राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी , राज्य सरकार द्वारा लागत साझेदारी परियोजनाओं में लागत साझेदारी राशि जमा कराने , परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग , विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियों , परियोजना(ओं) स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या , आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना(ओं) के समापन समय और लागत को प्रभावित करते

s.k

हैं। इस प्रकार इस स्तरर पर परियोजना को पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। उपर्युक्त बाधाओं के बावजूद, परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) से (छ): नई रेल लाइन परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार सर्वेक्षण/स्वीकृत किया जाता है न कि जिला-वार/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार क्योंकि रेलवे के सर्वेक्षण/परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

सिवनी और बालाघाट जिलों सहित मध्य प्रदेश में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली कुल 2679 किमी लंबाई की 16 नई लाइन का सर्वेक्षण पिछले तीन वर्षों अर्थात 2019-20, 2020-21, 2021-22 और चालू वित्त वर्ष 2022-23 में पूरे किए गए हैं। सिवनी और कटंगी (92 किमी) के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण को वित्त वर्ष 2020-21 में मंजूरी दी गई थी । इस लाइन का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

नई लाइन परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम स्थान संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, सामाजिक आर्थिक तथ्यों आदि, के आधार पर शुरू किया जाता है जो चालू परियोजनाओं की देयताओं, निधियों की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है। ऐसे क्षेत्र जो रेल नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं, उन क्षेत्रों में रेल अवसंरचना परियोजनाओं की स्वीकृति देना भारतीय रेल में निरंतर और सतत् प्रक्रिया है।

******

s.k